



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032025-261714
CG-DL-E-20032025-261714

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 18, 2025/ फाल्गुन 27, 1946

No. 80]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 18, 2025/ PHALGUNA 27, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2025

मामला सं. एडी (ओआई) – 02/2025

विषय : चीन जन. गण. और थाईलैंड साम्राज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलियोल" के आयातों से संबंधित पाटन रोधी जांच की शुरूआत के संबंध में।

1. फा. सं. 6/02/2025—डीजीटीआर – समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' कहा गया है) के अनुसार, मेसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'आवेदक' कहा गया है) द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' कहा गया है) के समक्ष, चीन जन. गण. और थाईलैंड साम्राज्य (जिसे इसके बाद 'संबद्ध देश' कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित स्लैबस्टॉक पॉलियोल (जिसे इसके बाद 'एफएसपी' अथवा 'संबद्ध वस्तुएं' अथवा 'विचाराधीन उत्पाद' के रूप में कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने और पाटन रोधी जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटित किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। तदनुसार, आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद "फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलियोले" है, जिसे संक्षेप में एफएसपी के रूप में कहा जाता है। यह 3000-4000 मॉलिक्यूलर भार का एक स्पष्ट चिपचिपा लिक्विड पॉलिमर होता है जिसे एक ट्रायोल चैन स्टार्टर के साथ प्रोपाइलीन ऑक्साइड और एथिलीन ऑक्साइड को पॉलिमर करके निर्मित किया जाता है। यह एक पॉलीइथर है और केटेलिस्ट एवं एडिटिव के साथ प्रतिक्रिया करने पर पॉलियूरेथेन फोम उत्पन्न करता है जिसका उपयोग अपहोल्स्ट्री, मेट्रेस, तकिए, बोल्स्टर, ट्रांसपोर्ट सीटिंग और पैकेजिंग में किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त प्रमुख कच्चे माल प्रोपलीन ऑक्साइड और एथिलीन ऑक्साइड हैं।
4. संबद्ध वस्तुओं को दिनांक 1 फरवरी 2022 से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 39 अर्थात् "प्लास्टिक और तत्संबंधी वस्तुएं" के अंतर्गत शीर्ष 3907 और टैरिफ मद 3907 29 10 और 3907 29 90 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्पाद को आंशिक क्षति अवधि अर्थात् 1 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक के लिए उप शीर्ष 3907 20 के अंतर्गत भी आयात किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
5. आवेदक ने इस अवस्था में किसी पीसीएन का प्रस्ताव नहीं किया है। वर्तमान जांच में शामिल पक्षकार इस जांच की शुरुआत होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और पीसीएन, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

6. आवेदक ने दावा किया है कि उसके द्वारा उत्पादित उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, अनुप्रयोगों और अंतिम उपयोगों, कीमतों आदि सहित सभी भौतिक पहलुओं में विषयगत देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के साथ तुलनीय हैं। ग्राहक इन उत्पादों का परस्पर उपयोग करते हैं।
7. तदनुसार, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात भौतिक अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तु तकनीकी और व्यावसायिक दृष्टि से संबद्ध देशों से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद के साथ प्रतिस्थापन करने योग्य है। अतः वर्तमान जांच शुरू करने के प्रयोजन से, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के "समान वस्तु" मानी गई है।

ग. घरेलू उद्योग और आधार

8. नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग इस प्रकार है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं समझा जाएगा।"

9. यह आवेदन मेसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि वह संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातक से संबंधित नहीं है।
10. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक के पास संबद्ध वस्तुओं के कुल भारतीय उत्पादन का 100% हिस्सा है। इसे देखते हुए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के संदर्भ में पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

11. वर्तमान पाटन रोधी जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन. गण. और थाईलैंड साम्राज्य हैं।

ड. जांच की अवधि

12. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 (12 माह) है। क्षति जांच की अवधि में 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 और जांच की अवधि शामिल होगी।

च. कथित पाटन का आधार**i. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य**

13. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं, तब तक उनके सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुलग्नक-1 के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।
14. आवेदक ने यह दावा किया है कि उसके पास किसी उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमतों अथवा लागत अथवा किसी उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से अन्य देशों में निर्यातों की कीमत के संबंध में सूचना तक पहुँच नहीं है। तदनुसार, आवेदक ने भारत में भुगतान योग्य कीमत, उसके उत्पादन की लागत और उचित लाभ के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य की गणना की है।

ii. थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य

15. आवेदक ने यह दावा किया है कि उसके पास घरेलू बिक्री कीमत के किसी साक्ष्य या थाईलैंड में उत्पादकों के उत्पादन की वास्तविक लागत के बारे में सूचना नहीं है। इस प्रकार, आवेदक ने अपने उत्पादन की लागत के आधार पर भारत में भुगतान योग्य कीमत के आधार पर एक सामान्य मूल्य की गणना की है, जिसमें लाभों को उचित रूप से शामिल किया गया है।
16. वर्तमान जांच शुरुआत के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने दोनों संबद्ध देशों के लिए आवेदक द्वारा निर्धारित सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

iii. निर्यात कीमत

17. संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत संबद्ध वस्तुओं की सीआईएफ कीमत पर विचार करके निर्धारित की गई है, जैसा कि डीजीसीआई एंड एस के आयात संबंधी डेटा में सूचित किया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बंदरगाह व्यय, अंतर्देशीय माल भाड़ा और बैंक शुल्क के संबंध में कीमत समायोजन किया गया है ताकि कारखाना बाह्य निर्यात कीमत निकाली जा सके। संबद्ध देशों के लिए दावा की गई निर्यात कीमतों के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

iv. पाटन मार्जिन

18. संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर की गई है, जो *प्रथम दृष्टया* यह दर्शाता है कि पाटन मार्जिन *न्यूनतम* स्तर से अधिक है और संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद को निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

19. आवेदक ने यह स्थापित करते हुए *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य प्रदान किया है कि संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। आयातों की मात्रा में क्षति की अवधि के दौरान निरपेक्ष रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत के संदर्भ में काफी वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से आयातों की कीमतों में काफी गिरावट आई है तथा संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आ रही है तथा उन पर दबाव डाल रहे हैं और कीमतों में कमी कर रहे हैं। इसके अलावा, संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की लागत से कम है तथा घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्रियों की लागत से भी कम है। इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में गिरावट आई है, जिसके

परिणामस्वरूप इसके बाजार अंश में भी गिरावट आई है। इसके चलते वस्तुसूचियों में काफी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि पाटित किए गए आयातों की मौजूदगी के चलते काफी वित्तीय हानि, नकदी हानि और निवेशों पर नकारात्मक प्रतिफल हुआ है।

20. अतः इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से पाटित किए गए आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

21. घरेलू उद्योग की ओर से अथवा उसके द्वारा दायर किए गए विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर तथा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करते हुए, जो संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा ऐसे पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को प्रमाणित करता है तथा नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए जांच की शुरुआत करते हैं तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करते हैं, जिसे यदि लगाया जाता है तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

झ. प्रक्रिया

22. वर्तमान जांच में नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना की प्रस्तुति

23. निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्राचार ईमेल पते <dir13-dgtr@gov.in> और <ad12-dgtr@gov.in> पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए, जिसकी एक प्रति <dir15-dgtr@gov.in> और <consultant-dgtr@nic.in> को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुति का वर्णनात्मक भाग सर्च योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड फॉर्मेट में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल फॉर्मेट में हों।
24. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकार और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को, जिन्हें संबद्ध वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाना जाता है, उन्हें अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी संगत सूचना दाखिल कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित फार्म और तरीके से दाखिल की जानी चाहिए।
25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना में निर्धारित फार्म और तरीके से इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर वर्तमान जांच के संबंध में प्रस्तुति कर सकता है।
26. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका एक अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराना आवश्यक है।
27. हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अद्यतन सूचना के साथ-साथ जांच से संबंधित आगे की प्रक्रियाओं की जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in>) को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय सीमा

28. वर्तमान जांच के संबंध में कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ई-मेल <dir13-dgtr@gov.in> और <ad12-dgtr@gov.in> पर भेजी जानी चाहिए, साथ ही उसकी एक-एक प्रतिलिपि <dir15-dgtr@gov.in> और <consultant-dgtr@nic.in> को उस तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए, जब घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से दायर आवेदन का अगोपनीय पाठ निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रसारित किया जाएगा अथवा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त हुई सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमों के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय-सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करें।
30. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर प्राप्त होना चाहिए।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

31. जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचना के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसका पालन न करने पर प्रतिक्रिया/अनुरोध अस्वीकृत किए जा सकते हैं।
32. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को बिना ऐसे अंकन के प्रस्तुत किए गए कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना मानी जाएगी तथा प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
33. गोपनीय पाठ में वह सभी सूचना शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की हैं, तथा/ अथवा अन्य सूचना, जिसे ऐसी सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना के लिए, जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि वह गोपनीय प्रकृति की है, अथवा ऐसी सूचना जिसके बारे में अन्य कारणों से गोपनीयता होने का दावा किया जाता है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण बताना भी आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
34. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होनी चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः अनुक्रमित अथवा रिक्त स्थान दिया जाना चाहिए (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित रूप से संक्षेपित किया जाना चाहिए, जिस पर गोपनीय होने का दावा किया गया है।
35. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझने के लिए अगोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना सारांश करने योग्य नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए इस तरह का सारांश प्रस्तुत करना संभव नहीं है, इसके कारणों का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए।
36. हितबद्ध पक्षकार अनुरोध के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाए की तारीख से 7 दिनों के भीतर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
37. गोपनीयता के दावे पर नियम 7 के अनुसार सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा पर्याप्त और पर्याप्त कारण कथन के बिना प्रस्तुत किया गया कोई भी अनुरोध, और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई उचित व्यापार सूचना को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
38. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध उचित नहीं है अथवा यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्यीकृत करने अथवा सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकता है।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

39. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, और साथ ही उन सभी से यह अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध के गोपनीय पाठ को सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। अनुरोधों के गोपनीय पाठ को प्रसारित न करने पर हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ड. असहयोग

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उपयुक्त समय अवधि के भीतर अथवा प्राधिकारी द्वारा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच प्रदान करने से इनकार करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2025

Case No. AD (OI)-02/2025

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Flexible Slabstock Polyol” originating in or exported from China PR and Kingdom of Thailand - *reg.*

1. **F. No. 6/02/2025-DGTR** - An application has been filed by M/s Manali Petrochemicals Limited (hereinafter referred to as the ‘applicant’) before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’), for initiation of an anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on imports of Flexible Slabstock Polyol (hereinafter referred to as ‘FSP’ or ‘subject goods’ or ‘product under consideration’), originating in or exported from China PR and Thailand (hereinafter referred to as the ‘subject countries’).
2. The applicant has alleged that injury is being caused to the domestic industry due to the alleged dumped imports of the product under consideration. Accordingly, the applicant has requested for the imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration is “Flexible Slabstock Polyol”, abbreviated as FSP. It is a clear viscous liquid polymer of molecular weight 3000-4000 manufactured by polymerization of propylene oxide and ethylene oxide with a triol chain starter. It is a polyether and on reaction with catalysts and additives, yields polyurethane foams which is used in upholstery, mattresses, pillows, bolsters, transport seating and packaging. The major raw materials used in the production process are propylene oxide and ethylene oxide.
4. The subject goods are classified under Chapter 39 *viz.*, “Plastics and articles thereof”, of the Customs Tariff Act under heading 3907 and tariff item 3907 29 10 and 3907 29 90, with effect from 1st February 2022. Additionally, the product has also been imported under the sub heading 3907 20 for part of the injury period, i.e., 1st April 2021 to 31st January 2022. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
5. The applicant has not proposed any PCN at this stage. The parties to the present investigation may provide their comments, on the scope of the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.

B. LIKE ARTICLE

6. The applicant has claimed that the products produced by it are comparable in all material aspects, including the physical and chemical properties, applications and end uses, prices, etc. with the product under consideration imported from the subject countries. The customers use the products interchangeably.
7. Accordingly, it is noted that there are no known material differences in the article produced by the domestic industry and the product under consideration exported from the subject countries. The article produced by the domestic industry and the product under consideration imported from the subject countries are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The article manufactured

by the domestic industry are technically and commercially substitutable with the product under consideration imported from the subject countries. Therefore, for the purpose of initiation of the present investigation, the article produced by the domestic industry has been considered as “like article” to the product under consideration being imported from the subject countries.

C. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

8. Rule 2(b) defines domestic industry as follows:

"Domestic industry" means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry."

9. The application has been filed by M/s Manali Petrochemicals Limited. The applicant is the sole producer of the like article in India. The applicant has submitted that it is not related to any exporters of the subject goods from the subject countries or importer of subject goods in India.

10. The Authority notes that the applicant accounts for 100% of the total Indian production of the subject goods. In view of the same, the Authority notes that the applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

D. SUBJECT COUNTRIES

11. The subject countries for the present anti-dumping investigation are China PR and Kingdom of Thailand.

E. PERIOD OF INVESTIGATION

12. The period of investigation for the purpose of the present investigation is 1st October 2023 to 30th September 2024 (12 months). The injury investigation period will cover the period 1st April 2021 to 31st March 2022, 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024 and the period of investigation.

F. BASIS FOR ALLEGED DUMPING

i. Normal value for China PR

13. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the subject goods. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure-I to the Rules.

14. The applicant has claimed that it did not have access to information with regard to prices or cost in an appropriate market economy third country, or price of exports from an appropriate market economy country to other countries. Accordingly, the applicant calculated the normal value for China PR based on the price payable in India, based on its cost of production plus reasonable profits.

ii. Normal value for Thailand

15. The applicant has claimed that it did not have access to any evidence of domestic selling price or information regarding actual cost of production of the producers in Thailand. Thus, the applicant calculated a normal value based on the price payable in India based on its own cost of production, with a reasonable addition of profits.

16. For the purpose of the present initiation, the Authority has considered the normal value as determined by the applicant for both of the subject countries.

iii. Export price

17. The export price of the subject goods has been determined by considering CIF price of the subject goods, as reported in the DGCI&S import data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight and bank charges to arrive at ex-factory export price. There is sufficient evidence of export prices claimed for subject countries.

iv. Dumping margin

18. The normal value and export price of the subject goods have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above *de-minimis* level and is significant in respect of product under consideration from the subject countries. Thus, there is *prima facie* evidence that the product under consideration from subject countries is being dumped by the exporters in the Indian market.

G. INJURY AND CAUSAL LINK

19. The applicant has provided *prima facie* evidence establishing that the subject imports have caused injury to the domestic industry. The volume of imports has increased significantly over the injury period both in absolute terms and in relation to production and consumption in India. The price of the imports from the subject countries has declined significantly and the subject imports are undercutting and are suppressing and depressing the prices of the domestic industry. Further, the subject imports are priced below the cost of the domestic industry and even lower than the raw material cost of the domestic industry. The production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry declined over the period, as a result of which its market share also declined. This has resulted in significant piling up of inventories. The domestic industry has claimed that the presence of dumped imports has resulted in significant financial losses, cash losses and negative return on investments.
20. Therefore, there is sufficient *prima facie* evidence that injury is being caused to the domestic industry by the dumped imports from the subject countries.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

21. On the basis of the duly substantiated application filed by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted, substantiating dumping of the product under consideration from the subject countries, injury to the domestic industry and a causal link between such dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

22. The principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed in the present investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

23. All communication should be sent to the Designated Authority *via* email at the email addresses <dir13-dgtr@gov.in> and <ad12-dgtr@gov.in> with a copy to <dir15-dgtr@gov.in> and <consultant-dgtr@nic.in>. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
24. The known producers/exporters in the subject countries, the government of the subject countries through its embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
25. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
26. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
27. Interested parties are further advised to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in>) for any updated information as well as further processes related to the investigation.

K. TIME LIMIT

28. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority *via* email at the email <dir13-dgtr@gov.in> and <ad12-dgtr@gov.in> with a copy to <dir15-dgtr@gov.in> and <consultant-dgtr@nic.in> within 30 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by or on behalf of the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.
29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (*including the nature of interest*) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

30. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

31. Where any party makes any confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the same may lead to rejection of the response / submissions.
32. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
33. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
34. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (*where indexation is not possible*) and such information must be appropriately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
35. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
36. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the interested parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the submission.
37. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
38. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

39. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTRs website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions might lead to consideration of an interested part as non-cooperative.

N. NON-COOPERATION

40. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority